भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2105 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्ग 37 और 58 की स्थिति

† 2105. श्री अरुण भारती :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग 37 (गंडक नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग 58 (कोसी नदी) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जलमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त जलमार्गों पर कार्गो और यात्रियों की आवाजाही के लिए क्या संभावनाएं तलाशी गई हैं;

(घ) इन मार्गों को प्रचालित करने के लिए फ्लोटिंग जेटी और नौचालन सहायक उपकरण विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त नदियों का उपयोग करते हुए नेपाल के साथ विकसित किए जा रहे किसी सीमा-पार अंतर्देशीय जल व्यापार प्रोटोकॉल की स्थिति क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): गंडक नदी और कोसी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) - 37 और राष्ट्रीय जलमार्ग - 58 घोषित किया गया था। रा.ज.-37 (गंडक नदी) पर मंगलपुर (नौतन) में और बेतिया के विपरीत किनारे पर दो जेट्टी स्थापित की गई हैं। 2013 में बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अद्यतन करने के लिए 92.75 लाख रुपए की लागत पर मैसर्स रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा लिमिटेड (आरआईटीईएस) को नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ने 2024 में रा.ज.-58 (कोसी नदी) में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया, और इस नदी को कार्गो आवाजाही के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

(ग): गंडक नदी पर कार्गो और यात्री परिवहन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मैसर्स आरआईटीईएस को डीपीआर के उन्नयन का कार्य सौंपा गया है।

(घ): रा.ज.–37 (गंडक नदी) को चालू करने के लिए, मंगलपुर (नौतन) में और बेतिया के विपरीत किनारे पर दो सामुदायिक जेट्टी स्थापित की गई हैं। चूंकि कोसी नदी (रा.ज.-58) को माल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, इसलिए फिलहाल कोसी नदी के लिए किसी गतिविधि की योजना नहीं है।

(ङ): कार्गो के परिवहन के लिए जलमार्ग सहित मार्गों को भारत सरकार और नेपाल के बीच पारगमन संधि में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

*****